जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

जालोर

Rashtradoot

फोनः- 226422, 226423 फैक्सः- 02973-226424 वर्षः 19 संख्याः 83 प्रभात जालोर, शनिवार 29 जून, 2024 पो. रजि. /RJ/SRO/9640/2022-24 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

लोकसभा में राहुल गाँधी व राज्यसभा में खड़गे का माइक ''म्यूट''?

सोशल मीडिया पर दिनभर वायरल रही यह खबर

-रेण मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 जून। क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वयं अपने दुश्मन बन गए हैं? क्या उनकी ज़िद भाजपा को क्षति पहुँचा रही है और ऐसा परिदृश्य पैदा कर रही है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि, वो आम आदमी के मुद्दों के साथ जुड़े हुए नहीं हैं?

भाजपा के एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा कि, यदि संसद में नीट के मुद्दे पर बहस की अनुमति दे दी जाती तो यह भाजपा के हित में होता और एक बार जब मुद्दे पर पूरी तरह बहस हो जाती तो उसको लेकर जो दबाव बन रहा है वो थोड़ा कम हो जाता और ऐसा लगता है कि, भाजपा इस मुद्दे को लेकर चिंतित है तथा देश के युवाओं के लिए बोल रही है।

लेकिन, हुआ क्या? ओम बिड़ला तथा जगदीप धनखड़ ने विपक्ष को यह मुद्दा उठाने नहीं दिया।

लोकसभा में विपक्ष के नेता, राहुल गाँधी का माइक स्विच ऑफ था और यह खबर अब वायरल हो गई है। ओम बिड़ला का कहना है कि, उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि माइक का बटन उनके पास नहीं है।

- **सूत्रों के अनुसार, राहुल गाँधी ने जब लोकसभा में नीट फर्जीवाड़े का मुद्दा उठाया तो, उनका माईक कथित तौर पर स्विच ऑफ था, जब राज्यसभा में खड़गे ने यही मुद्दा उठाया तो उनका माईक भी म्यूट था।**
- **राहुल गाँधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ने इस पर गंभीर आपत्ति जताई।**
- **इस मसले पर भाजपा में भी सुगबुगाहट देखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार, एक वरिष्ठ भाजपा सांसद ने कहा कि, संसद में नीट पर बहस की अनुमति दे दी जाती तो नीट मसले पर बढ़ता दबाव कुछ कम हो जाता और युवा वर्ग में मैसेज जाता कि भाजपा को उनकी फिक्र है।**
- **एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि, मोदी यह दिखा रहे हैं कि, सब कुछ उनके नियंत्रण में है, और कुछ भी नहीं बदला।**
- **विपक्ष के एक वरिष्ठ नेता ने यह भी कहा कि, अगर मोदी अपने तौर तरीके बदल लेते तो यह मैसेज जाता कि वे ''कमजोर'' हो गए हैं, शायद इसीलिए मोदी पुरानी कार्यशैली पर ही चल रहे हैं।**

मल्लिकार्जुन खड़गे को उठकर सदन के वैल में जाना पड़ा क्योंकि, राज्य सभा में जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के नेता को बोलने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया और उनका माइक भी म्यूट कर दिया गया।

एक वरिष्ठ नेता ने कहा, मोदी यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि, सब कुछ 17वीं लोकसभा जैसा ही है, कुछ भी बदला नहीं है। यह भी कि, सब कुछ उनके आदेश अनुसार ही होता है।

विपक्ष के एक नेता का कहना है कि, यह काल्पनिक परिदृश्य भाजपा को अधिक हानि पहुँचाएगा, जितना मोदी को अहसास भी नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि, मोदी हिले हुए हैं। वो अभी भी विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं देने की पुरानी रणनीतियों पर चल रहे हैं। माइक म्यूट कर देना और पूरी ताकत से अपना एजेण्डा आगे बढ़ाने जैसी युक्तियाँ अब सशक्त व मौन नेता की छवि को लाभ नहीं पहुँचा रही है।

अब यदि मोदी किसी अलग अवतार में आते हैं तो यह ऐसा होगा मानो वो स्वीकार कर रहे हैं कि, अब वो एक कमज़ोर नेता हैं जो बैसाखी के सहारे चल रहा है तथा स्वयं अपनी नियति का मालिक नहीं है।

लेकिन संसद के पिछले कुछ दिन दर्शाते हैं कि, मोदी अपनी काल्पनिक दुनिया में रहना चाहते हैं, फिर चाहे पार्टी को कुछ भी नुकसान हो।

एकलपट्टा केसों की जांच के लिए समिति गठित

जयपुर, 28 जून। प्रदेश में एकल पट्टों से संबंधित प्रकरणों की निष्पक्ष जांच के लिए राज्य सरकार ने समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर पूर्व न्यायाधीश आर.एस. राठौड़ की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है। साथ ही, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव इस समिति के सदस्य होंगे।

उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती सरकार

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पूर्व न्यायाधीश आर. एस.राठौड़ की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की और कहा कि एकल पट्टा केसों की निष्पक्ष जांच होगी।**

के कार्यकाल में एकल पट्टा प्रकरण में हुई अनियमितताओं पर न्यायालय से केस वापिस लेने के लिए कमेटी गठित की गई थी। लेकिन कमेटी में तत्कालीन शहर विकास मंत्री शांति धारीवाल के कार्यालय से संबंधित अधिकारियों को शामिल किया गया था। इससे उक्त कमेटी की निष्पक्षता पर सवाल उठे थे।

पूर्व न्यायाधीश आर.एस. राठौड़ की अध्यक्षता में नव गठित समिति

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अंततोगत्वा 5 महीने बाद रिहा हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन

झारखंड हाईकोर्ट ने सोरेन को जमानत देते हुए कहा कि, उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मनी लॉण्डरिंग का कोई केस नहीं बनता है

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 जून। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मनी लॉन्डरिंग केस में हाई कोर्ट से जमानत मिल जाने के बाद उन्हें रांची की बिरसा मुण्डा जेल से रिहा कर दिया गया। यह घटना राजनीति में इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस बात की पूरी संभावना है कि कुछ माह बाद प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में इंडिया ब्लॉक मजबूत होगा।

जैसे ही सोरेन जेल से बाहर निकलकर आए उनके पक्ष में जे.एम.एम. के हजारों समर्थकों ने जश्न मनाया और उनके पक्ष में नारे लगाए।

जेल से रिहाई के बाद मीडिया से बात करते हुए सोरेन ने कहा ''मुझे 5 माह तक जेल में रखा। हम यह भी गौर से देख रहे हैं कि न्याय प्रक्रिया में महीने या कुछ दिन ही नहीं बल्कि वर्षों का समय लग रहा है। आज संपूर्ण देश के लिए यह एक संदेश है कि हमारे खिलाफ एक षडयंत्र रचा गया था।''

''जो संघर्ष हमने शुरू किया था और जो संकल्प हमने लिए थे उनको मूर्तरूप देने के लिए हम काम करेंगे।''

- **हाईकोर्ट की सिंगल जज बैंच ने सोरेन को 50 हजार रुपये के बेल बॉण्ड और इतनी ही राशि के दो मुचलकों पर जमानत दी।**
- **ई.डी. ने यह कहकर जमानत का विरोध किया कि, सोरेन प्रभावशाली व्यक्ति हैं और रिहा होकर वे अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर सकते हैं। पर हाईकोर्ट ने कहा कि, सोरेन प्रथम दृष्टया अपराधी नहीं हैं और जमानत मिलने के बाद उनके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।**
- **झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को ई.डी. ने जमीन के एक सौदे में मनी लॉण्डरिंग की जांच के दौरान इसी वर्ष 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। तब से सोरेन रांची की बिरसा मुंडा जेल में ही थे।**

सोरेन को जमानत उनकी याचिका पर सुनवाई व कोर्ट द्वारा दो सप्ताह तक आदेश सुरक्षित रखने के बाद दी गई है।

न्यायाधीश रोंगोन मुखोपाध्याय की एकल बैंच ने सोरेन को 50,000 रूपये के एक जमानत बाँड एवं इतनी ही राशि के दो मुचलकों पर जमानत मंजूर की है।

सोरेन के वकील ने मीडिया से कहा कि कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री को प्रथम दृष्टया दोषी नहीं माना है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'पशु चिकित्सकों की रिटायरमैंट आयु 62 साल क्यों नहीं'

जयपुर, 28 जून (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने पूछा है कि पशु चिकित्सकों की रिटायरमैंट आयु सीमा 60 साल क्यों है 62 साल क्यों नहीं। हाई कोर्ट ने इस मामले में अतिरिक्त मुख्य वित्त सचिव, प्रमुख कार्मिक सचिव और संयुक्त पशुधन सचिव सहित चिकित्सा सचिव से जवाब तलब

- **राजस्थान हाईकोर्ट ने अतिरिक्त मुख्यसचिव, प्रमुख कार्मिक सचिव और संयुक्त पशुधन सचिव से जवाब मांगा है। ज्ञातव्य है कि, एम.बी.बी.एस. चिकित्सक 62 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं, पर पशु चिकित्सकों को 60 वर्ष की आयु में रिटायर कर दिया जाता है।**

किया है। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने यह आदेश डॉ. पदमचंद जैन व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। अदालत ने इन अधिकारियों से पूछा है कि जब एम.बी.बी.एस. चिकित्सकों की

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विधानसभा चुनाव में स्टालिन का सिरदर्द बनेंगे तमिल सुपरस्टार विजय

तमिलनाडू के इस लोकप्रिय स्टार ने साफ कर दिया है कि, वे तमिलनाडू विधानसभा चुनाव लड़ेंगे

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 जून। फिल्म अभिनेता विजय, तमिलनाडू में नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री के नियंत्रण में द्रमुक और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के कथित रूप से विफल रहने के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने इस पर आश्चर्य व्यक्त किया है कि ''राज्य के सभी ईमानदार और सत्यनिष्ठ लोग क्या कर रहे हैं।''

विजय ने सभी राजनीतिक दलों को एक ही लकड़ी से हांकते हुए कहा कि राजनीति में अच्छे लोगों की जरूरत है। चैन्नई में आयोजित छात्रों के एक अभिनन्दन कार्यक्रम में दिए गए संबोधन में विजय ने राज्य की राजनीतिक दुर्दशा पर टिप्पणी की और उनकी इस टिप्पणी को लोकसभा और विधानसभा के अगले चुनावों के मद्देनज़र चुनावी तैयारी के रूप में देखा जा रहा है।

- **विजय ने इन दिनों तमिलनाडू के मुख्यमंत्री व द्रमुक के मुखिया एम.के. स्टालिन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और आरोप लगाया है कि, सरकार नशीली दवाओं के कारोबार पर नियंत्रण करने में बुरी तरह नाकाम रही है।**
- **तमिलनाडू की राजनीति हमेशा से तमिल फिल्म इंडस्ट्री का प्रिय मैदान रही है। करूणानिधी, एम.जी. रामचंद्रन, सभी का फिल्मों से गहरा जुड़ाव रहा है, और अब एक्टर विजय भी इस क्षेत्र में जोर आजमाना चाहते हैं।**
- **विजय युवा वर्ग में बेहद लोकप्रिय हैं। हर धर्म और जाति के उनके प्रशंसक हैं। राजनीति में उनके आगमन की खबर से सत्तारुढ़ पार्टी में बैचेनी बढ़ने लगी है।**
- **विजय ने युवाओं में बढ़ती नशे की लत व नशे के कारोबार पर निशाना साधकर अपने इरादों का संकेत दे दिया है।**

विजय, तमिलनाडू की उन फिल्मी हस्तियों में से एक बनना चाहते हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुँचकर बड़ा नाम कमाया है। एम.जी. रामचन्द्रन और उनके संरक्षण में रहीं, जे. जयललिता तथा द्रमुक सुप्रीमो एवं पटकथा लेखक, एम. करूणानिधि,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'मनी लॉण्डरिंग रोकने में भारत विश्व में सबसे आगे'

अंतर्राष्ट्रीय संस्था, फाइनैंशियल एक्शन टॉस्क फोर्स ने कहा कि, भारत के वित्तीय नियम और पूंजी प्रवाह पर निगरानी करने वाली संस्थाएं काफी सशक्त हैं

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 जून। भारत को एक ऐसे देश के रूप में मान्यता मिली है जो मनी लॉण्डरिंग और टैरर फण्डिंग की गतिविधियों की रोकथाम में वैश्विक रूप से अग्रणी है। भारत के वित्तीय नियमन तथा वित्तीय त्रुटियों की निगरानी का सिस्टम भारत के और यहाँ आने वाली बकायदा वित्तीय गड़बड़ियों को दूर करने में प्रभारी रूप से काम करते हैं।

भारत को यह मान्यता, पूरी दुनिया और देशों के भीतर मनी लॉण्डरिंग, टैरर फायनैंसिंग व अनियमित वित्तीय त्रुटियों की रोकथाम करने वाली एक वैश्विक संस्था फायनैंशियल एक्शन टॉस्क फोर्स (एफ.ए.टी.एफ.) ने दी है। यह अंतर सरकारी संस्था एक वैश्विक निगरानी एजेंसी है। भारत को सिंगापुर के एक विशेष एकांश द्वारा पारस्परिक मूल्यांकन के बाद ''रैग्यूलर फॉलोअप'' श्रेणी में रखा गया। यह श्रेणी पर्यवेक्षण और जाँच के स्वीकार्य मापदण्डों की एक मान्यता है।

इस प्रकार की मान्यता उपयोगी है क्योंकि यह मान्यता मिलने के बाद देश को वित्तीय सैक्टर के ग्लोबल प्लेयर्स के लिए सुरक्षित गंतव्य माना जाता है। इससे देश की व्यापारिक संस्थाओं की वैश्विक वित्तीय बाजारों तक पहुँच में भी सुधार होता है।

- **फाइनैंशियल एक्शन टॉस्क फोर्स (एफ.ए.टी.एफ.) टैरर फंडिंग, मनी लॉण्डरिंग और विभिन्न देशों से होने वाले गैर कानूनी वित्तीय लेन-देन पर नज़र रखती है।**
- **भारत 2010 में इस संस्था में शामिल हुआ था, तबसे ही भारत में गैर कानूनी वित्तीय प्रवाह पर कड़ा नियंत्रण रखा जाता है।**
- **भारत ने अधिकांश अन्तर्राष्ट्रीय अकाउन्टिंग स्टैण्डर्ड्स अपना रखे हैं जो बेहद कठोर हैं।**

यह वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेन्सीज़ से उच्च क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करने के समान है। एफ.ए.टी.एफ. से मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी देश को ग्लोबल अकाउन्टिंग स्टैण्डर्स भी व्यवहार में लाने पड़ते हैं।

भारत ने वर्षों पहले, अधिकांश इन्टरनैशनल अकाउन्टिंग स्टैण्ड्र्स अपना लिए थे, जो व्यवहारिक रूप से थोड़े सख्त होते हैं। एफ.ए.टी.एफ. का व्यवहारिक उपयोग वश्विक आतंकवाद के प्रसार के विरोध में 1990 के दशक में शुरु किया गया था। पश्चिमी देशों ने आरंभ में इसकी शुरुआत ऑर्गनाइज़ेशन कोर इकोनॉमिक को-ऑपरेशन एण्ड डवलपमैंट (ओई.सी.डी.) के नेतृत्व में की थी।

कुछ ही अन्य देशों को भारत जैसी श्रेणी में रखा गया है।

पाकिस्तान ने प्रायः सीमा पार आतंकवाद को प्रोत्साहित किया है और ऐसी बेहिसाब वित्तीय त्रुटियों में उनकी भागीदारी रही है। मनी लॉण्डरिंग की रोकथाम में पाकिस्तान की एफ.ए.टी.एफ. रैकिंग बहुत नीचे है।

वित्तीय सहायता व संसाधन उपलब्ध कराए बिना सीमा पार आतंकी गतिविधियां नहीं हो सकतीं। ऐसी गतिविधियां को फण्डिंग करने का प्रत्यक्ष परिणाम है वैश्विक आतंकवाद। भारत वर्ष 2010 में एफ.ए.टी.एफ. बिरादरी का हिस्सा बना था और वह तब से ही अनियंत्रित वित्तीय गड़बड़ियों पर कठोर प्रतिबंध लगाता रहा है। एक सदस्य देश के रूप में भारत मनी लॉण्डरिंग और टैरर फण्डिंग के खिलाफ उपाय करने को बाध्य है।

टैलिकॉम कंपनियों ने मोबाइल रीचार्ज 27% तक महंगा किया

नई दिल्ली, 28 जून। देश की दोनों ही प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों जियो और एयरटेल ने अपने रीचार्ज प्लान्स की कीमतों में इजाफा कर दिया है। जियो ने करीब ढाई साल बाद अपने रीचार्ज प्लान्स कीमतों में इजाफा किया है। जहां एयरटेल ने अपने प्लान्स को 600 रुपये

- **जियो ने रीचार्ज प्लान में 12-27 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है तथा एयरटेल ने अपने रीचार्ज प्लान्स को 600 रुपये तक महंगा कर दिया है।**

तक महंगा किया है, वहीं जियो के प्लान्स की कीमतों में 27 परसेंट तक की बढ़ोतरी हुई है।

दोनों कंपनियों ने 5 जी सर्विस लॉन्च के बाद अपने प्लान्स में ये बड़ी बढ़ोतरी की है। इससे पहले भी टेलीकॉम कंपनियों ने कुछ प्लान्स को रिवाइज किया था, लेकिन इस बार पूरे

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दो राजनैतिक घटनाक्रमों से तिलमिलाए नीतीश दिल्ली पहुँचे

आज होने वाली जद (यू) की नैशनल एग्ज़िक्युटिव बैठक में नीतीश बड़ा बयान दे सकते हैं

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 जून। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दल (यूनाइटेड) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए आज दिल्ली पहुँचे। बैठक शनिवार को शुरु होगी। यह बैठक हाल ही की दो महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं की पृष्ठभूमि में हो रही है। नीतीश सरकार ने आरक्षण कोटा में बढ़ाने की जो घोषणा की थी, उसे पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और दूसरी घटना है, भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे द्वारा हाल ही में दिया गया वक्तव्य, जिसमें उन्होंने कहा है कि, भाजपा को 2025 का विधानसभा चुनाव स्वयं अपने बल पर लड़ना चाहिए।

हाई कोर्ट के आदेश से जहाँ नीतीश कुमार बचाव की मुद्रा में आ गए हैं, वहीं, चौबे की टिप्पणियाँ ऐसे समय में शर्मिंदगी का कारण बनी हैं, जबकि, नरेन्द्र मोदी सरकार अपने सरवाइवल के लिए मुख्य रूप से नीतीश की पार्टी पर निर्भर है।

- **नीतीश कुमार के आरक्षण कोटा बढ़ाने के फैसले को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है, जिससे नीतीश की भारी किरकिरी हुई है।**
- **नीतीश को आशंका है कि, कि हाईकोर्ट इस फैसले से राष्ट्रीय जनतादल के नेतृत्व वाले महागठबंधन को लाभ होगा। इसी से आशंकित होकर वे विधानसभा चुनाव एक साल देरी से, महाराष्ट्र, हरियाणा व झारखंड के चुनावों के साथ, कराने पर जोर दे रहे हैं।**
- **भाजपा ने ना केवल नीतीश के इरादों पर चुप्पी साध रखी है, बल्कि भाजपा के एक वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे ने तो यह तक कह डाला कि, भाजपा को विधानसभा चुनाव अकेले लड़ना चाहिए।**
- **इससे यह संकेत मिलता है कि, बिहार में भाजपा और जद (यू) के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, जबकि केन्द्र में भाजपा सरकार नीतीश के समर्थन पर आश्रित है।**
- **समझा जाता है कि, नीतीश इस मसले को प्रधानमंत्री मोदी व गृहमंत्री अमित शाह के समक्ष उठाएंगे, साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ऐसी रणनीति पेश करेंगे जिससे जद (यू) तथा उनकी खुद की प्रासंगिकता बनी रहे।**

संभावना है कि, अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग में चौबे की टिप्पणी का मसला उठाएंगे।

जद (यू) के दो नेताओं (राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह और राम नाथ ठाकुर) को मोदी के मंत्रिमण्डल में शामिल किया गया है और जद (यू) ने स्पीकर के लिए भाजपा की पसंद, ओम बिड़ला का समर्थन भी किया है।

लेकिन, बिहार में भाजपा और जद (यू) के बीच सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इस बारे में अटकलबाजिया उस समय शुरु हुईं जब, भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कॉल आने पर जल्दबाजी में एक महत्वपूर्ण मीटिंग छोड़कर चले गए। यह मीटिंग भाजपा महामंत्री विनोद तावडे ने हाल में संपन्न लोकसभा चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए बुलाई थी तथा मीटिंग में नवम्बर 2025 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों के लिए रणनीतियों पर भी चर्चा होनी थी।

आरक्षण के मामले पर हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद आर.जे.डी. के नेतृत्व वाले महागठबंधन की लोकप्रियता में वृद्धि होने की आशंका में कुमार इस अनुचित मांग पर दबाव देते रहे हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव एक वर्ष के लिए टाल दिए जाए और बिहार चुनाव महाराष्ट्र, हरियाणा व झारखण्ड में होने वाले चुनावों के साथ कराए जाए। भाजपा इस विचार पर शांत है।

कल होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कुमार प्रभावी रणनीति के साथ आने का प्रयास करेंगे ताकि उनकी पार्टी और उनकी स्वयं की राजनीतिक प्रासंगिकता बरकरार रहे।

कुमार को एक चतुर नेता के रूप में जाना

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बारिश का पानी शशि थरूर के घर में घुसा

नई दिल्ली, 28 जून। दिल्ली में शुक्रवार को हुई बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया। सड़कों पर वाहन पानी में डूबे नजर आए। भारी बारिश के कारण दिल्ली की सड़कों पर कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम भी नजर आया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बारिश की वजह से अपने लुटियंस दिल्ली के घर में फिर से पानी भर जाने की कहानी

- **शशि थरुर ने कहा, मैंने सुबह उठकर देखा तो मेरे घर के हर कमरे में एक फुट पानी था।**

एक्स पर शेयर की। उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि, सुबह जागने पर उनके घर के हर कमरे में एक फुट पानी था।

एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा, ''कारपेट्स, फर्नीचर, बिल्कुल हर चीज खराब हो गई। शायद मोहल्ले के स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज भर गए थे, इसलिए पानी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)